बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि २२ फरवरी, १९६० को पूर्वाह्न ९ बजे उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह के सभापतित्व में हुआ ।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद ।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1960-61.

*श्री सभापति सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने बजट भाषण के सिलसिले में

खेती की पैदावार के विषय में कह रहा था । सरकार का कहना है कि कभी पैदावार के लिये मौसिम अनुकूल रहता है तो कभी प्रतिकूल, कभी फसल अधिक पैदा होती है तो कभी कम । साल-ब-साल सरकार इसपर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन उसके विषय में सरकार नहीं बताती है कि उसकी ओर से जो खाद का प्रबंध किया गया, बीज दिया गया या सिंचाई का प्रबंध किया गया उससे पैदावार बढ़ी है या नहीं । सरकार की ओर से गेहूँ का बीज देने की बात कहीं गई है बजट भाषण में । माननीय सदस्यों को पता होगा कि उस बीज से पैदावार बढ़ी है या घटी है । मेरा तो अपना अनुभव है कि जहां राजस्थानी बीज दिया गया है वहां पर जमीन परती पड़ी रह गई । मेरे क्षेत्र में ३०–४० एकड़ जमीन में यह बीज बोया गया था, असेम्बली क्वेश्चन द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और यहां पर माननीय उपमंत्री महोदय ने खुद कहा कि हम जाकर देखेंगे । वहां, जहां पर अच्छा बीज सरकार की ओर से दिया गया, जमीन परती रह गई और जहां स्थानीय बीज बोया गया वहां अच्छी फसल पैदा हुई । उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसी तरह से कागजी घोड़ा दौड़ा कर कह दिया जाय कि पैदावार बढ़ी है तो यह गलत है । मैं फीगर के आधार पर बतलाना चाहता हूँ कि १९४६-४७ से १९५७-५८ तक साल-ब-साल किस तरह इस सरकार के रेजीम में पैदावार घटी है । कतकी धान जहां १९४६-४७ में ५ लाख ६७ हजार सौ १०० टन पैदा हुआ था वहीं १९४७-४८ में ५ लाख ३० हजार ४०० टन, १९५०-५१ में २ लाख ५ हजार ५५० टन और १९५४-५५ में १ लाख ७२ हजार ९५३ टन धान की पैदावार हुई । यानी जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से पैदावार घटती गई । जहां अंग्रेजों के समय में यहां ५ लाख टन की पैदावार थी वह घट कर इनके राज्य में एक लाख पर पहुँच गई और बहुत कोशिश करने के बाद १९५७-५८ में ये २ लाख १३ हजार १२० टन तक पैदावार बढ़ा पाये हैं । इतना ही नहीं सरकार की ओर से कितने नये विभाग खोले गये, अच्छे बीज कहकर दिये गये, करोड़ों रुपये खर्च किये गये लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती गई । उसी तरह विन्टर राइस की ओर भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जहां १९४७-४८ में २० लाख ६८ हजार १०० टन और १९४९-५० में ३५,२२,५६२ टन धान पैदा हुआ था वहीं वह घट कर १९५१-५२ में २६ लाख ४६ हजार ७६७ टन पर पहुँच गया और वह घटते-घटते १९५७-५८ में

श्री राम जनम ओझा—सब-जुडिश होने के लिये किन-किन बातों को देखा जाता है, उसके कौन-कौन-से हालत होते हैं, उसको देखने से मालूम होता है कि यदि किसी इजलास में कोई मुकदमा हो, डिपाटमेंटल इनक्वायरी न हो, उसमें कोई मुद्दई और मुद्दालह हो, पर इसके लिये इजलास का होना जरूरी है। इन चीजों से उनके केस का पूरा या इसका कुछ भी अंश ताल्लुक रखता है या नहीं यह देखना है। यदि ये बातें हैं, ऐसा ये साबित कर सकें तो यह सब-जुडिश है। एस० डी० ओ० के यहां तो ऐसी हर बात का इनफोर्मेशन होता ही है।

उपाध्यक्ष—पर यदि एस० डी० ओ० ने कौगनिजेंस लिया हो तो सब-जुडिश हो जायगा।

श्री राम जनम ओझा—यदि एस० डी० ओ० ने कौगनिजेंस लिया है तो नम्बर आफ दी केस क्या है।

(जवाब नहीं दिया गया।)

उपाध्यक्ष—टिफिन के बाद में इस पर रूलिंग दूंगा।

श्री शिव महादेव प्रसाद—कम-से-कम अभी मोशन को पढ़ दिया जाय।

उपाध्यक्ष—पहले से इस सदन का कनवेन्शन रहा है जब तक अध्यक्ष कनविन्स्ड नहीं हो जाता है कि यह मानने लायक है तब तक वह नहीं पढ़ा जाता है, मुझे इस कनवेन्शन की रक्षा करनी है। जब मैं कनविन्स्ड हो जाऊंगा कि यह एलाऊ हो सकता है तो पढ़ दिया जायगा।

श्री रामचरित्र सिंह—रिसेस के बाद इस पर रूलिंग दे दिया जाय यही ठीक है।

उपाध्यक्ष—३ बजे में इस पर रूलिंग दूंगा।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR, 1960-61.

श्रीमती पार्वती देवी—आज सरकार बड़े पैमाने पर कृषि के ऊपर ध्यान दे रही है और आगे के लिये भी बहुत-सी अच्छी-अच्छी योजनायें बना रही है इसलिये मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। आज कृषि की समस्या ही हमारे राज्य की समस्याओं में एक बड़ी समस्या है, कृषि की समस्या को हल करने के बाद ही हम राज्य में अनेक समस्याओं का हल कर सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि कृषि प्रोत्साहन में, कृषि उत्पादन में जिस तरह बड़े-बड़े किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, छोटे-छोटे किसानों को भी जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या एक बिगहा दो बिगहा जमीन है उनको भी प्रोत्साहन देने की कोशिश करें। जिनके पास एक या दो बिगहा जमीन

है वे बोरिंग या पम्पिंग सेट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जब कृषि विकास का काम कर रहे हैं तो बड़े किसान और छोटे किसान दोनों के लिये एक ही व्यवस्था रहे तभी हम असली रूप में कृषि का विकास कर सकेंगे। आज छोटे किसान आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि जिनके पास कम जमीन है उनको कुछ जमीन देकर, बोरिंग या पम्पिङ्ग सेट की व्यवस्था कर कृषि में प्रोत्साहन दें। जितनी योजना सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिये बनायी है उसमें अगर अधिकारीवर्ग कुशलता और तत्परता से काम करें तो अवश्य ही कृषि के मामले में हम आगे बढ़ सकेंगे और खेती का विकास कर सकेंगे।

दूसरी चीज में सरकार से कहूँगी कि हमारे मनिहारी थाने में तीन साल से ५ बांध को लेकर इतनी क्षति हो रही है जिसके लिये सरकार को भी हर साल कर्ज तथा रिलीफ देना पड़ रहा है। इसके बारे में मैं सदन में बराबर सवाल भी पूछती हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पांचों बांध के टूटने से मनिहारी थाने की करीब-करीब ५० हजार की क्षति हुई है जिसको देखने के लिये अग्रिकल्चर मिनिस्टर गत जुलाई में वहां गये थे। उन्होंने जिलाधीश के सामने आश्वासन दिया कि पांचों बांध को जहां तक होगा पूरा करने की चेष्टा की जायगी। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि उसे जल्द पूरा करें ताकि उसे भविष्य में रिलीफ तथा कर्ज नहीं देना पड़े। इन बांधों को पक्का बना दिया जाय। उन पांचों बांधों के नाम हैं : एकदिगरी, गोविन्दपुर, चौरा, दमड़िया तथा....

अगर सरकार वहां बांध बना दे तो मनिहारी थाने में कभी भी फसल नहीं मारी जा सकती है। साथ ही साथ में सरकार से निवेदन करूंगी कि मनिहारी थाने के किसान एक और बात से तबाह हैं। वह यह है कि मनिहारी थाने के गोविन्दपुर बस्ती बंगाल और बिहार के बोर्डर पर है। बंगाल सरकार दावा करती है कि वह क्षेत्र हमारा है और बिहार सरकार कहती है कि हमारा है। अभी तक मालगुजारी बिहार सरकार ले रही है लेकिन जब किसान अपने खेतों पर अपनी फसल काटने या लगाने जाते हैं तो बंगाल वाले उस पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं, कभी-कभी तो बंगाल वाले धान उठाकर भी ले जाते हैं। बोर्डर पर बंगाल की मिलिट्री रहती है जो किसानों को वहां से धान की फसल नहीं लाने देती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि दोनों सरकार विचार-विमर्श करके जनता को इस तकलीफ से मुक्ति दिलावें। जब तक यह फैसला अन्तिम रूप से नहीं हो जाता है तब तक वहां के किसानों के सामने काफी दिक्कतें बनी रहेंगी और खेत भी परती रह जायगा।

मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण को सुनकर मुझे काफी खुशी हुई है। उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि प्रकृति ने मुझे साथ दिया है कि जिसकी वजह से हमारी अगहनी फसल अच्छी हुई है लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि सरकार को सिर्फ प्रकृति के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रहना चाहिये। आज हमारी बैशाखी फसल सूख रही है। इसलिये मैं सरकार से चाहूँगी कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसानों को प्रकृति के भरोसे न रहना पड़े।

जनस्वास्थ्य विभाग के मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत से हास्पिटल का प्रान्तीयकरण किया है लेकिन कटिहार अस्पताल में अभी तक बिजली भी नहीं पहुँचायी गयी है जब कि आपरेशन के समय बिजली से काफी सम्बन्ध रहता है। आज तक वहां एक्सरे भी नहीं होता है, एक्सरे की मशीन गयी है लेकिन जब से गयी है तब से वह मशीन बेकार पड़ी हुई है। जहां हजारों आदमी के जीवन-मरण का सवाल रहता है, वहां इन सब कामों के लिये सरकार को देर नहीं करनी चाहिये।

अभी वेलफेयर मंत्री जी तो सदन में नहीं हैं फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये में निवेदन करूंगी कि हमारे थाने में वेलफेयर का जो कुछ भी काम हुआ है वह नहीं के बराबर ही है। हरिजनों के लिये संविधान में कुछ सुविधायें दी गई हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिये में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये। हमारे राज्य में भिखमंगे की भी बड़ी जटिल समस्या होती जा रही है। यह किसी भी राज्य के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती है। राज्य में हर व्यक्ति के लिये सुख और सुविधा समानता के आधार पर होनी चाहिये।

आज पटने शहर में करीब २० हजार व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं, यह भी जन स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। उनके स्वास्थ्य के लिये भी सरकार को कदम उठाना चाहिये तथा साथ ही साथ में यह भी अनुरोध कर देना चाहती हूँ कि अब रिक्शा चालकों को नयी लाइसेंस न दी जाय। देश में आजादी मिलने के बाद हर चीज की सुख-सुविधा जनता को मिलनी चाहिये। देश में या राज्य में कोई न भिखमंगा रहे और न कोई ज्यादा अमीर रहे इस बात का भी ख्याल सरकार को करना चाहिये।

अब मैं लोक-निर्माण विभाग की बात भी कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन मंत्री जी तो नहीं हैं पर उप-मंत्री जी हैं। अभी हमारे क्षेत्र में एक भी लोक-निर्माण विभाग की सड़क नहीं है। मंत्री महोदय से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कटिहार-मनिहारी रोड बनेगी, उन्होंने वचन दान तो दिया है लेकिन देखना है कि कबतक बनती है। मैं उनका ध्यान कटिहार-अमदाबाद रोड की ओर भी ले जाना चाहती हूं। जब कभी मैं उस रास्ते से चलती हूं तो मुझे रास्ते में ही रुक जाना पड़ता है। वह सड़क इतना खराब है कि रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाती है। अगर सरकार सचमुच देहातों का विकास चाहती है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस सड़क को प्रमुखता दे। समय चूंकि कम है इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं और उन्होंने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं हृदय से उनका आभारी हूं।

*श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इच्छा इस बजट के

अधिवेशन में बोलने की नहीं थी और न मैंने साल भर के अन्दर कोई बड़ा भाषण ही दिया है। बात यह है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे मुझे और बिहार की जनता को कुछ क्षोभ हुआ है और मैं समझता हूं कि उसमें कुछ गलतफहमियां हो गयी हैं जिन्हें मैं साफ कर देना चाहता हूं। क्षुब्ध जनता की ओर से मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे भाषण का दो मुख्य विषय होगा, एक भूमिहार राज्य और दूसरा अफसरी राज्य। उसके बाद कुछ छोटी-मोटी चीजों पर बोलूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि जब आपको मालूम होगा कि मैं बेकार की बातों को बोल रहा हूं तो उसी समय आप मुझे रोक देंगे और मैं बैठ जाऊंगा। मैं हरिजन राज्य पर भी बोलूंगा।

बात यह है कि कुछ दिनों से मैं बतला रहा हूं, यहां का एक सम्मानीय समाचार पत्र है, उसके सम्पादक हमारे मित्र हैं, वे हमारे भूमिहार-राज की बहुत शिकायत करते रहे, उस अखबार में किसी दिन ऐसा नहीं होता कि उसमें राज (भूमिहार राज) के बारे में न निकलता हो और निकलता है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि बदमाश भूमिहार के हाथ में राज्य है, मित्र के विरोध में मैंने कुछ नहीं कहा। अभी हाल में शिवहर थाने से जो माननीय सदस्य आये हैं जिनके बाप के साथ हमारी भैयारी थी, जिनको मैं अपने लड़के की तरह मानता हूं उन्होंने और पुपरी के सदस्य ने ऐसी बात कही कि हमारी समझ में यह बात आई कि इस वक्त बोलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता हूं कि भूमिहार राज्य का अर्थ क्या है?

श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—मैंने भूमिहार राज्य का इस्तेमाल नहीं किया है।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—खैर इसके बारे में मैं नहीं कहता कि क्या आप कहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी राज्य का अर्थ क्या होना चाहिये। जातिवाद के आधार पर पक्षपात करते हों, सारी चीजें अपने लिये रखते हों या दूसरा यह भी हो सकता है कि राज्य में केवल भूमिहार ब्राह्मणों को फायदा होता हो, दूसरों को फायदा न होता हो तो निःसन्देह यह विचार करने योग्य बात है। इसीलिये मैं इस विषय को लेना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर भूमिहार ब्राह्मण हैं, उन्हें अपने ईमान का ऐसा ख्याल होता है कि आर्डर पास करने के वक्त कहीं मुझसे गलती न हो जाय। चीफ मिनिस्टर भूमिहार ब्राह्मण हैं लेकिन उनकी मिनिस्टरी को ही लें जिसमें राजपूत मिनिस्टर हैं, कायस्थ मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर लोग भी भिन्न-भिन्न जाति के हैं। मुठ्ठी भर कायस्थ मेम्बर हैं, मुठ्ठी भर कायस्थ इस राज्य में हैं, फिर भी मिनिस्ट्री में इस जाति से एक व्यक्ति रखे गये हैं। आपके मुसलमान मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर हैं लेकिन भूमिहार ब्राह्मण मिनिस्टर नहीं हैं। मैं जो बात कहता हूं उसको गौर से सुनें.......................

श्रीमती सुन्दरी देवी—माननीय सदस्य ने मुठ्ठी भर कायस्थ की बात तो कही लेकिन मुठ्ठी भर मुसलमान की बात नहीं कही।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—मुट्ठी भर कायस्थ तो हैं लेकिन वे काफी एडुकेटेड और प्रभावशाली हैं। हीरा मुठ्ठी भर ही होता है और राख छँटी भर, फिर मुठ्ठी भर अगर हीरा हो तो क्या वह बहुत नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों की यही हालत है।

अब आप सेक्रेटेरिएट स्तर पर आयें। जबसे डा० श्रीकृष्ण सिंह का राज्य हुआ है, एक भूमिहार ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी नहीं हुआ, राजपूत हुआ, मद्रासी हुआ, बंगाली हुआ, यह भी बात नहीं है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति के कोई व्यक्ति योग्य नहीं हैं इसलिये इस जाति के चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाये गये। जितने सेक्रेटरीज हैं उनमें ७५ प्रतिशत नन-भूमिहार ब्राह्मण हैं। मुख्य मंत्री के पर्सनल स्टाफ की ओर देखें, इनके सेक्रेटरी कायस्थ, प्राइवेट सेक्रेटरी मुसलमान, जैसा कि धारणा है कि प्राइवेट सेक्रेटरी अपनी जाति का बनाना चाहिये वह यहां नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को देखें, यह एक बड़ी जगह है जहां से लोगों की बहालियां होती हैं। उसमें श्री रजनधारी सिंह थे जिनको अंग्रेजों ने बनाया था। उसमें कुरमी आये, राजपूत आये लेकिन भूमिहार ब्राह्मण नहीं आये। कमिश्नरी में आयें, चार कमिश्नरियां हैं। चारों में एक भी भूमिहार ब्राह्मण कमिश्नर नहीं है। कलक्टरों में भी सबसे कम संख्या भूमिहार ब्राह्मणों की है। युनिवर्सिटी में आयें, सर सी० पी० एन० सिंह वाइस-चान्सलर थे, उनकी बहाली सर रदरफोर्ड ने की थी। जब से कांग्रेस सरकार आई तब से एक भी भूमिहार ब्राह्मण वाइस-चान्सलर नहीं हुआ है। तीन कायस्थ वाइस-चान्सलर हो गये, मद्रासी हो गये, पंजाबी हो गये, राजपूत हुए लेकिन एक भी भूमिहार ब्राह्मण वाइसचान्सलर नहीं हुए।

अब आप आइये जो सबसे बड़ा स्थान है, प्रोविन्स का सिविल हाई कोर्ट उस पर। श्रीबाबू के समय में कम से कम १२ जजों की बहाली हुई है। मैथिल ब्राह्मण चीफ जज हुए, दो तीन राजपूत जज हुए, कायस्थ हुए, मारवाड़ी हुए लेकिन एक भूमिहार ब्राह्मण जो पहले से जज था और वह रिटायर कर गया तब उसके स्थान पर एक भूमिहार ब्राह्मण की बहाली हुई।

एक माननीय सदस्य—बहाली कैसे होती है ?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—बहाली होती है चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की राय से और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेंगे तो हाई कोर्ट का जज नहीं बहाल होगा।

राज्य ट्रांसपोर्ट जो एक भूमिहार ब्राह्मण के हाथ में था, उसका फीगर मैंने लिया है। फैक्ट फीगर में झगड़ा क्या है, माननीय सदस्यों को अधिकार है फीगर कलेक्ट करें, दो और दो-चार ही होगा, तीन नहीं। सिर्फ जवाब देने से तो नहीं होगा। ७ प्रतिशत उसमें भूमिहार ब्राह्मण हैं। भूमिहार जाति के लोग नगण्य हैं इस प्रांत में ऐसी बात तो नहीं है कि फिर इसको भूमिहारों की तरफदारी कही जायेगी या दूसरी चीज कही जायेगी ? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने, मैनेजर हुए और उनमें ८० प्रतिशत नन-भूमिहार ब्राह्मण, जो भी बड़े अफसर हुए उनमें ९० प्रतिशत नन-भूमिहार ब्राह्मण हुए। अन्य विभागों में जाइये, पी० डब्लु० डी० बहुत कमाने वाला विभाग है, इसमें चीफ इन्जीनियर डिप्टी चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, एक्जेक्युटिव इन्जीनियर लोग हैं तो इनमें भूमिहार कहां हैं ? तो कहने का मतलब यह है कि जब ईमानदारी से काम हो रहा है तो फिर गलत बात क्यों कही जाती है ?

श्री कैलाशपति सिंह—बोर्ड जो बने हैं उसके बारे में कहा जाय।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—मैं सब बात कहूंगा। कोशी जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका अरबों और करोड़ों का खर्च है, जो टेंडर एक्सेप्ट करते हैं वे जाति के राजपूत हैं। डी० वी० सी० पर अरबों और करोड़ों रुपये खर्च हुए और हो रहे हैं जिसका चेयरमैन हमारे फूलन प्रसाद वर्मा थे। अब लीजिये खादी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट को। महेश बाबू इन्डस्ट्रीज के मिनिस्टर थे। उन्होंने योग्यतम लोगों की बहाली खादी बोर्ड में की। अगर भूमिहार ब्राह्मण कुछ हैं तो वे बहुत अच्छे हैं। आप देखिये, महेश बाबू ने खादी बोर्ड के जरिये लाखों आदमियों को इम्प्लायमेंट दिलाया है। लोगों को खादी पहनाया है। लाखों को परवरिश दी है, नौकरियां दी हैं।

अब राज्य ट्रांसपोर्ट बोर्ड बना। उसमें रामेश्वर प्रसाद सिंह को चेयरमैन बनाया गया। उनकी योग्यता आपको मालूम ही है। बृटिश जमाने में उन्होंने सी० आई० ई० की पदवी ठुकरा दी थी।

एक सदस्य—जरा किसानों के बारे में कहें।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—बहुत से अफसर ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर एक वक्त था जब गोलियां चलाये हुए थे और आज उन्हीं की तरक्की हुई है।

एक सदस्य—एलेक्ट्रिसीटी के बारे में कहिये।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—उसकी तो दूसरी बात है। अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। अभी तो जो अफसर हैं, वह है।

एक सदस्य—पटना कारपोरेशन में क्या हुआ ?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—मुझे ताज्जुब होता है कि जो चुनकर आता है उस पर भी आवाज कसी जाती है। अगर भूमिहार का लड़का पढ़ता है और उसमें योग्यता है तो वह हो सकता है। कहने वाले तो इतना तक कह गये हैं। प्रोफेसर रंगा जो स्वतंत्र पार्टी के प्रेसिडेन्ट हैं उन्होंने कहा है कि यह जो स्वतंत्र पार्टी बिहार में है वह एक जाति वालों की ओर से चलायी जा रही है। मैं कहता हूं कि यह गलत बात है। लेकिन रंगा ने इस तरह की बात कही है। तो मैं कहता हूं कि आपके हाई-कोर्ट के जज हैं उनमें भूमिहार एक थे और वे रिटायर किये हैं तो उनकी जगह पर एक हुए हैं। हाईकोर्ट में १२ जज हैं उसमें तो ज्यादा भूमिहार ही होना चाहिये था लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं इलाहाबाद जाता हूं। वहां मेरा घर भी है। वहां ५० प्रतिशत जज कायस्थ हैं सक्सेना, माथुर आदि तो उसको कोई नहीं कहता है। वहां राजपूत और भूमिहार का रेसियो नहीं है। जो योग्य होता है उसको हाईकोर्ट का जज बहाल किया जाता है। आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को पी० एच० डी० मिला और अमुक को नहीं तो यह कोई जवाब नहीं है। जो पढ़ता है वह डिग्री पाता है। इसको तो कोई नहीं कह सकता है कि युनिवर्सिटी बनाने वाला भूमिहार है। यह कहना कि सत्येन्द्र नारायण सिंह राजपूत हैं और राजपूत राज कायम करना चाहते हैं; के० बी० सहाय कायस्थ हैं और कायस्थ राज बनाना चाहते हैं और महेश बाबू भूमिहार ब्राह्मण राज कायम करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं इस चीज का स्वागत नहीं करता। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्षमा करेंगे। एक जगह मैं बैठा हुआ था। तीन चार भूमिहार ब्राह्मण बैठे हुए थे। उसमें यह चर्चा चल रही थी कि जजों में कोई भूमिहार नहीं है तो चीफ मिनिस्टर का मुंह तमतमा गया। बीच ही में हंस कर उनको रोक कर मैंने कहा कि आपलोग सूर्य पर कम-से-कम न थूकें। आप एस० के० सिंहा को गाली दीजिए लेकिन जाति की शिकायत नहीं कीजिए। आपलोग जाति को जो गाली देते हैं उसका असर जनता पर पड़ता है। तो मैं अपने आदरनीय साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि जातीयता की बात करते हैं तो उसका असर ग्रामीण जनता पर, जो सीधे साधे आदमी हैं पड़ता है। हमारे राज्य में कांग्रेस और सरकार दोनों एक ही चीज है। एक नीति निर्धारित करती है तो दूसरे पर उसका असर पड़ता है।

पं० मंत्रेश्वर शर्मा जो हमारे मित्र हैं और शायद कुछ लिखे-पढ़े भी हैं.........

श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—मेरा प्वायंट आफ आर्डर है और वह यह है कि जो व्यक्ति हाउस में नहीं है उसका जिक्र करना उचित नहीं है।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—पं० मंत्रेश्वर शर्मा बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे मित्र भी हैं। वे सर्चलाइट में लिखते हैं कि कांग्रेस डूब रही है। अब कांग्रेस को

बचाना चाहिये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जरा नजर उठाकर अपने पड़ोसी प्रांतों को देखिये।

श्री केदार नारायण सिंह आजाद—मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह बजट स्पीच हो रही है या राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जाति के ऊपर स्पीच हो रही है। हाउस में बजट पर बोलना चाहिये।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—आप उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्यप्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और बंगाल को देखें। वहां कांग्रेस का ही प्रशासन है। उसमें कितने लोग निकाले जाते हैं और लिये जाते हैं लेकिन बिहार ही एक ऐसा सूबा है जहां के नेता बराबर बरकरार हैं। हाल ही में चेयरमैन का एलेक्शन हुआ जिसमें ३०० आदमी में २९ आदमी वाक आउट किये।

मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में है, जो कांग्रेस लीडर का अपनी पार्टी में है बहुमत है वह हिन्दुस्तान के किसी प्रोविन्स में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इस राज्य में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत स्ट्रोंगर है और पोपुलर है।

श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—ऐसा कब से समझने लगे हैं?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—जबसे हमने अपनी अक्ल से काम लेना शुरू किया। सर्चलाइट के जरिये यह कहा जाता है कि दिल्ली वाले दौड़ेंगे, यहां कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। इसके कहने से कांग्रेस पार्टी का नुकशान होता है यदि आप कांग्रेस के सच्चे हितैषी हैं, अनडिसप्यूटेड और अनक्वालिफायड हैं। अभी तरह-तरह की पार्टी है। मैं शर्मा जी की शिकायत नहीं करता हूं बल्कि प्रार्थना करता हूं कि आप जो कांग्रेस के प्रति यह प्रोपेगेंडा करते हैं वह सही नहीं है। इसको बन्द करें। आपके जरिये से जात-पांत का भेदभाव शुरू हो गया है। एक जाति दूसरे जाति के विरोध में खड़ी होती जा रही है।

श्री मृत्युंजय सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वायन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। वह यह है कि जो आदमी इस सभा में मौजूद नहीं है उसके प्रति इस तरह की धमकी देना क्या वाजिब है?

उपाध्यक्ष—यह कोई प्वायन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—अब मैं अफसरों के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। अभी जो पुराने आई० सी० एस० अफसर्स हैं उसमें से ज्यादातर लोग मेरे दोस्त हैं। वे लोग हमलोगों का आदर करते हैं। मैं भी जानता हूं कि वे मुल्क को आगे बढ़ाने में, अपने प्रोविन्स को सुन्दर बनाने में काफी दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं जो अपनी अफसरी को संसार में कायम करना चाहते हैं। अफसर-संसार यही है कि वे छः बजे तक काम करते हैं सही, उनके पास फाइलें भी बहुत रहती हैं लेकिन उसका रीजल्ट दूसरा ही होता है। रिजल्ट यह होता है कि कोई काम जल्दी से नहीं होता। मैं चाहता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि काम जल्द हो

यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आराम हराम है। यह सब कोई जानते हैं कि काम के एक्जेक्यूशन में बहुत डिले होता है। इसके कई कारण हैं। मेरा अपना ख्याल है कि एक ही विषय का कई विभागों के जरिये जो रीएक्जामिनेशन होता है वह भी डिले का एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि आजकल अफसरों की टेंडेंसी हो गयी है कि मिनिस्टरों को किसी तरह से सबोटेज करना या बेहूदा बना सकें तो अच्छा है। यह अनपार्लियामेंटरी है। अगर कहा जायगा तो मैं विथड्रॉ कर लूंगा। वे अपना अलग संसार बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष---आर्डर, आर्डर, शब्द "बेहूदा" अनपार्लियामेंटरी है, इसको माननीय सदस्य विथड्रॉ कर लें।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह---मैं इसे वियड्रॉ करता हूं। इस तरह से देर करने से काम में हर्ज होता है। यह वेलफेयर स्टेट है। आजकल अफसरों में यह टेंडेंसी हो गई है कि हम ऐसा करें जिससे हमको कोई पकड़ नहीं सकें। लेकिन काम जल्द हो इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता और मिनिस्टरों को जो सहयोग उन्हें देना चाहिये नहीं देते हैं।

श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह---अगर मिनिस्टर गलत काम करना चाहें तो?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह---हम किसी को गलत काम करने को नहीं कहते हैं लेकिन जल्दी करें और अपने विभाग के मिनिस्टर को सहयोग दें। अफसर दो क्लास के हैं। एक वे हैं जो सेक्रेटारियट में काम करते हैं और दूसरे वे हैं जो फिल्ड में काम करते हैं। बी० डी० ओ० भी फील्ड में काम करने वाले अफसर होते हैं। लेकिन आज जितने बी० डी० ओ० हैं उसमें सैकड़े ५० रहने के काबिल नहीं हैं। उन्हें न काम मालूम है और न वे चाहते हैं कि राज्य को आगे बढ़ने दें। आजकल इन लोगों का उद्देश्य हो गया है कि काम में रुकावट डालें, इसके अलावे वे कुछ नहीं करते हैं। वे असेम्बली के मेम्बरों को भी अपना सबार्डिनेट समझते हैं। आम तौर से इनके व्यवहार इस सदन के सदस्यों के साथ अच्छा नहीं होता है। बी० डी० ओ० के जरिये सरकारी पैसे का वेस्टेज होता है। सरकार को चाहिये कि उनके द्वारा सम्पन्न किये गये कामों का फिर से जांच कराये कि कहां सुधार हुआ है, कहां वेस्टेज हुआ है और कहां एकोनोमी की गयी है। अगर जांच करके देखा जायगा तो पता चलेगा कि हर जगह वेस्टेज ही हुआ है। एक बी० डी० ओ० हैं जिनकी बीबी को पान खाने का बड़ा शौक है। वे देहात में पोस्टेड हैं। शायद पाली में हैं। उनकी बीवी के लिये गवर्नमेंट जीप से रोज दानापुर से पान जाया करता है। शायद पान लगाने में दिक्कत होती है इसलिये छूटा पान भी नहीं बल्कि पान की गिलौरी जाती है दानापुर से उनके लिये। मुजफ्फरपुर के कमिश्नर एक दिन सिनेमा गये तो देखा कि वहां आठ-दस ब्लॉक की गाड़ी लगी हुई है। वे लोग देहात से सिनेमा देखने गवर्नमेंट जीप से आते हैं। इस तरह की बातें आजकल आपको अखबार में भी पढ़ने को मिला करेगी। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर जब कभी सरप्राइज विजिट में किसी ब्लॉक में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ताश खेल रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं। मगर जब खबर देकर जाते हैं तो हर तरह की तैयारी रहती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सरप्राइज विजिट ब्लॉक का करना चाहिये और प्रोग्राम देकर विजिट नहीं करना चाहिये।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहेब या दूसरे मिनिस्टर साहब अगर विजीट करना चाहें तो सरप्राइज विजीट करें प्रोग्राम बना कर नहीं जाना चाहिये। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक ब्लौक में दो-दो जीप अभी हैं वह वेस्ट है।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष महोदय, मैं ब्लौक के बारे में कह रहा था कि वहां बहुत वेस्टेज हैं, उसको कम करना चाहिये। मैं कह रहा था कि हरएक ब्लौक में दो-दो जीप हैं, एक ब्लौक के डाक्टर के लिये और एक ब्लौक डेव्हलपमेंट अफसर के नाम पर। ब्लौक का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। कहीं-कहीं हौस्पिटल भी है और इनडोर पेसेन्ट भी रहते हैं और जो लोग जीप रखते हैं उनको मालूम है कि तीन चार साल में वह खराब हो जाती है। इसका मतलब है कि १५ हजार रुपया इतने दिनों में बरबाद हो जाता है। इसके अलावा रिपेयर वगैरह में भी काफी खर्च होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक ही जीप से काम लिया जाय और डाक्टर और बी० डी० ओ० आपस में समय बांध लें और बारी-बारी से जीप का इस्तेमाल करें। इस तरह ो के बजाय एक जीप से काम चल सकता और इस तरह वेस्टेज जो है उसको कम किया जा सकता है। बी० डी० ओ० के हाथ में रेवेन्यु का काम जो दिया गया है इसीसे गोलमाल होता है। कलेक्शन के बारे में हरदम उनसे पूछा जाता है इसलिये वे उसमें ज्यादा समय देते हैं क्योंकि कलेक्शन कम करेंगे तो यह उनके सर्विस बुक में लिखा जायगा। इसलिये वे इसमें ज्यादा समय देते हैं। तो मैं कहूंगा कि पंचायतें काफी तयदाद में बनने वाली है और उन्हीं को रेवन्यु कलेक्शन का काम दे दिया जाय और बी० डी० ओ० को पूरा समय डेव्हलपमेंट के काम में लगाने के लिये कहा जाय। अभी बी०डी० ओ० जो हैं वे बिल्कुल इनएक्सपेरियन्सड हैं और निरे लड़के हैं। मैं चाहता हूं कि सिनियर अफसर हों उनको बी० डी० ओ० और पी० ओ० बनाया जाय और बी० डी० ओ० लोगों को लाकर उनसे इन्क्वायरी का काम लिया जाय। हमसे एकाध एस० डी० ओ० ने कहा है कि एस० डी० ओ० से बी० डी० ओ० होना अच्छा है।

दूसरी बात मुझको यह कहनी है कि पहले यह बात थी और मैंने चीफ सेक्रेटरी से हाल में बातें की तो मालूम हुआ कि आज भी वही बात है कि "होम डिस्ट्रीक्ट" में अफसरों को पोस्टिंग नहीं होनी चाहिये इसलिये कि जो अफसर होम डिस्ट्रीक्ट में रहता है उसको भी नुकसान है क्योंकि उसके गांव के लोग अकसर आते रहते हैं और वह परेशान रहता है। अगर जाँच की जाय तो मालूम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट में मिनोव्हर करके खासकर मिडल और लोअर क्लास के अफसर अपने जिले या सबडिवीजन में चले गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि उनको 'हरासमेंट' होता है और काम भी हर्ज होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात को एक्जामिन करे और जो लोग अपने जिले या सबडिवीजन में पोस्टेड हो गये हैं उनको दूसरे जिले या सबडिवीजन में भेजें।

इसके बाद मैं स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहना चाहता हूं। जिन-जिन विषयों पर मैं बोल रहा हूं उन सभी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लोग तो हैं नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार किया जाय। स्टेट ट्रेडिंग एक पौलिसी है जिसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं। स्टेट का काम ट्रेड करना नहीं है। हां, फूड-ग्रेन की कमी हो

जाय, फेमिन कंडीसन्स शुरू हो जायं तो आपको फूड-ग्रेन्स का इन्तजाम करना है। टैक्सेज आपको मिलना जरूरी है यह बात सही है। जो लोग ट्रेड करें उनको टैक्स देना जरूरी है। राज्य ट्रांसपोर्ट जब कायम हुआ था तो मैंने उसका विरोध किया था क्योंकि जो लोग अपना बस चलाते थे उनके कंडक्टर और ड्राइवर ऐसे होते थे जिनमें लोगों के प्रति अच्छा ट्रीटमेंट करने की एक भावना होती थी ताकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। राज्य ट्रांसपोर्ट का मोनोपोली होने से अब यह बात नहीं रह गयी। अब तो ट्रांसपोर्ट बोर्ड के एक चेयरमैन साहब भी बहाल हो गये हैं। मगर चेयरमैन या बोर्ड का काम यह होना चाहिये कि वह देखे कि जो वर्तमान बस सर्विस हैं वह ठीक से चल रही है या नहीं। क्या खामी है उसको हटाने की कोशिश की जानी चाहिये। लेकिन इसके बदले कहीं उनके ऊपर यह जुनून न सवार हो जाय कि कितना माइलेज बढ़ा। बम्बई में ट्रांसपोर्ट सिटी के अन्दर ही है और कलकत्ते में भी सिटी के अन्दर ही है। यू० पी० में ५० परसेन्ट से कम ही रोड पर राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं। इंगलैंड में ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था लेकिन अब उसका डिनेशनलाइज कर दिया है इसलिये कि इस ट्रेड से गवर्नमेंट को लौस होता है और लोगों को भी प्राइवेट ट्रेडिंग की इन्सेन्टिव्ह कम हो जाती है। ठीक है, रुपया लगाया है तो इसे कीजिये लेकिन इसको बढ़ाने की कोशिश मत कीजियेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की बसें चल रही थीं और उन्हीं से उनकी जीविका चलती थी और उस लाइन को आपने अगर ले लिया है तो आपको उसके लिये मुआवजा देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि इसमें मुकदमा हुआ है या नहीं। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि उनका मुआवजे का केस है। गवर्नमेंट कोई बनिया नहीं। गवर्नमेंट के साथ एक हाई मोरिलीटी की बात है। मुसीबत यह है कि अगर आप लाइन ले लेते हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी है और इसलिये मैं आपको कहता हूं कि आपको मुआवजा देना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह फूड एडलट्रेशन है। फूड एडलट्रेशन ऐक्ट है मगर उसमें कोई कारवाई होते नहीं देखता हूं। हर जगह जहां भी देखिये, मुजफ्फरपुर हाजीपुर, सभी जगह फूड एडलट्रेशन है। मेरा ख्याल है कि ऐक्ट में अगर सजा माइल्ड है तो सेक्शन को जरा और मजबूत बनाना चाहिये क्योंकि अभी लोगों का फूड एडलट्रेशन की वजह से स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और कोई कारवाई नहीं हो रही है।

हमारी सरकार मिथिला में एक युनिवर्सिटी कायम करने जा रही है और इसके लिये मैं अपनी ओर से और मिथिला के लोगों की ओर से इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वहां के लोगों की इस जरूरियात को पूरा किया गया।

अब मैं कुछ पटना और बिहार युनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कुछ नेता यह कहते हैं कि लड़कों और प्रोफेसरों को पोलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिये। मैं यह नहीं समझ सकता कि क्यों यह कहा जाता है क्योंकि ऐसा कह करके उनके अधिकार से वंचित क्यों करने की बात होती है। यह एक कंट्रोवर्सियल बात है और इसलिये मैं और ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन लड़कों में इनडिसप्लिन की बात उठायी जाती है और यह भी कहा जाता है कि पटना युनिवर्सिटी को टिचिंग युनिवर्सिटी इसी मकसद से बनाया गया था जिसमें वहां से अच्छी तरह से लड़के शिक्षित होकर निकलें। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है और सरकार का यह मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ? आज छात्रों की हालत यहां पर यह है कि जानवरों के रहने के लिये तो जगह का इंतजाम है लेकिन

हमारे छात्रों के रहने के लिये कोई इंतजाम नहीं है और फिर भी इस तरह की मांग करने के लिये यह कहा जाता है कि लड़के बड़े इनडिसिप्लिन्ड हैं। सरकार को तो उनके अभिभावक के समान रहने का हक है लेकिन फिर भी कोई इस बात को देखनेवाला नहीं है कि उनके रहने के लिये क्या इंतजाम है, उनके खाने और पढ़ने के लिये क्या इंतजाम है। इसलिये मेरा एक छोटा सा यह सुझाव है कि इस चीज पर छानबीन करने के लिये एक कमिटी बननी चाहिये जो ६ महीने के अन्दर ही विचार करके और सारी बातों की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दे और फिर यह सरकार उसको कोल्ड स्टोरेज में न देकर जल्द उस पर विचार करे और जो मांग जायज हो उसको पूरा करने के लिये कोशिश करे। इस कमिटी को ६ महीने का समय दिया जाय और उसके बाद १९६२ के चुनाव का इंतजार न किया जाय कि यह सरकार फिर आवेगी या कोई दूसरी सरकार आवेगी, बल्कि जो सुझाव हो उनको कार्यान्वित किया जाय।

इसके बाद सौभाग्य से हमारे मकबूल साहब यहां पर मौजूद हैं। वे हाल ही में जब हाजीपुर गये हुए थे तो वहां उन्होंने पाया कि सैकड़े ९५ कुंओं में खारा पानी है। वे वहां पर यह बोले थे कि वे जल्द ही पीने के लिये पानी का इंतजाम करेंगे लेकिन फिर भी नहीं मालूम होता है कि इस मामले में अब क्या हो रहा है। कहां पर यह फाइल अटकी हुई है और यदि कहीं पर यह अटकी हुई हो तो एक झटका देकर उसको आगे बढ़ाना चाहिये। ट्यूबवेल का इंतजाम करके ही पीने के पानी का इंतजाम कर सकते हैं।

इसके बाद आपके जरिये सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ ले जाना चाहता हूं। यहां पर उर्दू, मैथिल और बंगला भाषा भी हिन्दी के अलावे प्रचलित हैं। अभी बिहार युनिवर्सिटी से एक सरकुलर निकला था कि सभी ननलैंग्वेज विषय को हिन्दी में जवाब लिखना होगा और इस पर बहुत हल्ला हुआ। ठीक है कि इससे बंगाली और मुसलमान भाइयों को दिक्कत होती थी और अभी दो साल के लिये इस सरकुलर को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि दो वर्ष के बाद ही इस मसले का हल नहीं निलनेवाला है। उसके बाद भी यह सवाल रहेगा और इसलिये सरकार की एक पॉलिसी तय हो जानी चाहिए मुसलमान लड़कों को हिन्दी में लिखने में जरूर दिक्कत है। २५ वर्ष पहले ही कांग्रेस का एक प्रस्ताव पास हुआ था कि राष्ट्र भाषा के अलावे भी रेजिनल लैंग्वेज को भी सिखलाना चाहिये और यह मुनासिब भी था। जब कोई आदमी शिरवानी, कोई आदमी पैन्ट और कोई आदमी पायजामा पहन सकता है तो यह भी जरूरी है कि वह अपनी पसंद की भाषा भी बोल और लिख सके। उर्दू और मैथिल भाषा भी बहुत ही रीच भाषा हैं और बंगला साहित्य तो बहुत ही ऊंचा उठा हुआ है। हमारा ख्याल है कि सरकार की ओर से ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिये जिसमें इन भाषाओं के विकास में किसी तरह की बाधा पहुंचे। कुरान तो उर्दू में ही छपा है और इस तरह से उर्दू की पढ़ाई बंद होने से उसको कुरान पढ़ने में भी दिक्कत हो सकती है। जब देश आजाद हुआ है, तो इस तरह की कोई पॉलिसी न होनी चाहिये जिसमें किसी को कोई दिक्कत पैदा हो जाय और जो मेरिट है उसको डिमेरिट में बदल दिया जाय। सरकार की ओर से हिन्दी स्कूल खोलने की बात है और उसके लिये एक सर्वे भी हो चुका है। प्राइमरी शिक्षा कम्पलसरी और फ्री करने के सिलसिले में यह सर्वे हुआ है लेकिन ऐसा सर्वे उर्दू स्कूल खोलने के लिये नहीं हुआ है। पहले उर्दू के लिये एक इंसपेक्टिंग मौलवी होते थे जो मकतब की जांच करते थे लेकिन अब तो इस पोस्ट को तोड़ दिया गया है और इस तरह से उर्दू की सही तालीम

नहीं हो रही है क्योंकि हिन्दी जानने वाले इंसपेक्टर क्या समझ सकते हैं कि किस तरह से उर्दू की पढ़ाई हो रही है। इसी तरह से बंगला के लिये भी इंतजाम होना चाहिये। आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये न कि नीचे घटाने की ओर यदि खर्च का सवाल हो तो उससे हमको पीछे नहीं भागना चाहिये। हमारी कंस्टीच्युएन्सी में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर मुसलमानों की काफी संख्या है और वहां पर मकतब खोलने की बड़ी जरूरत है। इसलिये मैं सरकार से यह कहूंगा कि हिन्दी की तरह उर्दू के स्कूलों को खोलने का भी एक सर्वे होना चाहिये और उसी के मुताबिक स्कूल उर्दू के लिये खोलना चाहिये।

अब यह कहना चाहता हूं कि आये दिन हम अखबार में यह पढ़ते हैं कि अमुक अस्पताल से इतनी कीमत की दवाई गुम हो गयी यह एक गम्भीर बात है, सरकार को इसे मुस्तैदी के साथ देखना चाहिये कि क्यों ऐसा हो रहा है।

मेरा अपना अनुभव यह है कि ३०-३२ सालों से काउनसिल के मेंबर रहते हुए भी मुझे यह पता नहीं था कि हमको, और हमारे लड़के आदि सभी की दवा सरकार के यहां से मिलती है। पता यह लगा कि एक सज्जन जो एक साथी ही हैं, दो हजार की दवा अपनी बीमारी के लिए लिये। वे तो यहां हाजिर रहते थे लेकिन दवा भी लेते थे। दवा मिलने में सिर्फ वाउचर से काम भी चल जाता है। कोई भी काम हो उसका एक तरीका होना चाहिये। आगे उसको बदलने की जरूरत हो तो उस तरीके को बदलना भी चाहिये। पहले इस तरह का अवसर नहीं मिलता था। अंग्रेज लोग इस तरह का मैनिपुलेशन भी नहीं करते थे। इससे बचने का मेरा सजेशन यह है कि बेइमानी भी न हो और हम स्वास्थ्य भी रहें। इसमें जो नीचे के मुलाजिम हैं उनको ५, १०,२० रुपया एलाएन्स के तौर पर दवा के लिए दिया जाय। लेकिन सरकारी अफसरान जिनका मुशाहरा ५००-६०० रुपया है या असेम्बली या काउन्सिल के मेंबर हैं उनको दवा के लिए रुपया नहीं लेना चाहिये लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है और उनके लिए अगर चेयरमैन या स्पीकर कहें कि दवा मिलनी चाहिये तो उन्हें लेनी चाहिये।

अध्यक्ष—मुझे कहने का अधिकार नहीं है, चूंकि मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाता हूं।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—मैं यह कह रहा हूं कि मुझको।

श्री फजलुर्रहमान—और मंत्रियों के बारे में आपका ख्याल क्या है?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—माननीय मंत्रियों को भी नहीं लेनी चाहिये। जिनकी तनख्वाह ज्यादा है या जो सरकार के ऊपर के अफसरान हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिये।

I appeal to the good sense of the big officers and to the members of the House, through you Sir, that they should refuse to take this grant for medicines.

जो लोग सिपाही या नीचे के कर्मचारी हैं या किरानी हैं उनको यह इमदाद मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष—आपने अभी जो कुछ कहा है वह नहीं कहने के जैसा समझा जायगा ।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—यह आपका हुक्म है तो ठीक है । अब मैं

आपसे थोड़ा पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा अपना ख्याल है कि अगर सरकार बदनाम है तो इसके लिये सिर्फ पुलिस के नीचे तबके के अफसरों या बी० डी० ओ० वगैरह जवाबदेह हैं? नहीं तो पुलिस या सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकती हैं । लोगों का ख्याल है कि पुलिस विभाग में करप्शन है, यह एक बदगुमानी है और इसको रोकना चाहिये । कांग्रेस का या किसी का राज्य हो उसको कायम रखने के लिये अच्छी पुलिस की जरूरत है और सरकार ने इसी चीज को मद्देनजर रखकर एक पुलिस कमीशन भी मुकर्रर किया है उसकी मानी यही है कि उसमें रेडिकल सुधार होगा । उसके सूक्ष्मतम जांच की जायेगी । मुझे भी क्वेश्चनेयर मिला है । मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि पुलिस कमीशन ने एक उत्तम क्वेश्चनेयर तैयार किया है । हमारे सदस्यगण, चाहे वे यहां के हों या उस हाउस के, उन्हें यह खबर है कि क्वेश्चनेयर आया है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है । और उनसे यह रिक्वेस्ट किया गया कि वे इजहार देंगे तो उन्होंने नहीं दिया । मुझे क्वेश्चनेयर नहीं मिला तो मैंने उसे मंगाया । मार्च के फर्स्ट वीक तक में अपना एकजास्टिव एविडेंस देने का विचार रखता हूं । जहां कहीं किसी माननीय सदस्य ने किसी अफसर के खिलाफ कुछ कहा तो सरकार बिलकुल डिफेन्सिव एटिच्युड ले लेती है । माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि इसी फ्लोर पर मैंने एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ कुछ कहा था तो डिप्युटी मिनिस्टर ने कहा कि शायद इनकी सिफारिश को उसने नहीं सुना होगा इसीलिए ये उससे रंज हैं । मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि कोई अफसर यह बतलावें कि मैंने अपनी ४५ वर्षों के पब्लिक लाइफ में किसी अफसर के यहां कोई सिफारिश की है ? हमतो जनता के चुने हुए आदमी हैं इसलिये एस० पी० के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो तो सरकार को डिफेंड नहीं करना चाहिये बल्कि उसपर कार्रवाई करनी चाहिये । अगर मैं नहीं कहता तो सरकार उसकी एन्क्वायरी नहीं करती सरकार के सामने सारे फैक्टस भी नहीं आते, जिस डकैती के केस को उन्होने सप्रेस करना चाहा वह सब बात कोर्ट के सामने नहीं आती, जज ने भी सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ रिमार्क किया और जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट हुआ है, यह सब बात नहीं होती ।

श्री ठाकुर गिरजा नन्दन सिंह—उस आफिसर का प्रोमोशन हुआ या नहीं ?

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—न उसका प्रोमोशन हुआ और न डिमोशन ।

यह मैटर अपील में है । जब उसपर फैसला होगा तभी कोई कार्रवाई हो सकती है यह सभी लोग चाहते हैं कि स्टेट में अमन चैन कायम रहे इसलिए मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरह का डिफेन्सिव एटिच्युड इसतरह के मामले में न ले । एक बड़े लुत्फ की बात है जो सभी लोग सुनना चाहेंगे । मैं कल जब मजफ्फरपुर में था तो सोनवर्षा थाने का एक गरीब किसान मेरे यहां आकर मेरे पैरों में पड़कर कहा कि उसके यहां तीन चार हजार रुपये का जेवर जो उसकी स्त्री और पतोहू का था, चोरी हो गया। जब वह दारोगा जी के यहां उसकी इत्तला लिखवाने गया तो

दारोगा ने कहा कि एक सौ रुपया दो तो लिखेंगे। जब वह एक सौ रुपया नहीं दे सका तो उसने उस गरीब को बैठाकर थाने से चला गया। तो वह गरीब उस रोज दिनभर और रात भर तथा दूसरे दिन दो पहर तक बैठा रह गया। उसके बाद दारोगा आया तो उसकी कमर में रस्सा बांध कर उसे चालान कर दिया।

इस तरह का जुल्म तो हमने नहीं सुना कि जिसके घर में चोरी हो उसी को अरेस्ट करके भेज दिया जाय। हुजूर चार दिनों तक वह जेल में रहा, उसके बाद छूटकर आया है। इसके बाद सुना जाय, उस गरीब ने हमसे प्रार्थना यह की कि एक काम उसका करा दें। वह यह कि इस मामले की जांच खुद एस० पी० करें। मैंने एस० पी० को फोन किया और कहा कि मैं फौर एन्ड अगेंस्ट कुछ नहीं जानता लेकिन इतना सीरियस एलिगेशन सबइंसपेक्टर के खिलाफ है और एक गरीब जिस पर जुल्म हुआ है, वह कहता है कि एस० पी० इसकी जांच खुद करें। एस० पी० के हम बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने इस बात को कबूल किया और कहा कि मैं फौरन जा रहा हूं और एक घंटे के अन्दर वे चले भी गये। इसके बाद आगे क्या हुआ इसकी खबर अभी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, ऊपर के अफसर को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद हुजूर एक बात और यह है कि पहले १०, २० करोड़ रुपए का बजट बनता था लेकिन आज यह रकम १२०, १२५ करोड़ तक पहुंच गयी है, इस तरह एक्स-पैन्शन होता गया है। हुजूर, बहुत सी चीजों के लिए रुपयों की जरूरत है जिसमें काफी रुपया नहीं है। जैसे, सिंचाई के काम, पढ़ाई-लिखाई के काम में जितने रुपये होने चाहिए और जितना काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मेरा अनुभव यह है कि बहुत सी जगहों में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैपिंग है और वेस्टेज हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए जिससे ज्यादा लाभ सरकार को हो। फायदा यह होगा कि रुपया का रुपया बचेगा, तंगी दूर होगी और वेलफेयर का काम भी आप उससे कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक कमिटी इसके लिए तुरत मुकर्रर की जाय०जो दो बातों की जांच करे। एक तो यह है कि क्यों काम में देर होती है, कहां कहां डिफेक्ट है। कहां नया तरीका अख्तियार करना है और कहां पुराने तरीके को रीमोडेल करना है और दूसरी बात यह है कि कहां ड्यूटी ओवरलैपिंग है, क्यों काम बढ़ा हुआ है। वेस्टेज कहां है जिसको रोका जा सके। इसकी जांच करायी जाय और छः महीने के अन्दर रिपोर्ट मांगी जाय। मुमकिन है ऐसा करने से एक-दो करोड़ रुपए की बचत आप कर सकेंगे जिससे दूसरे काम किए जा सकते हैं।

श्री महावीर राउत—हुजूर, माननीय सदस्य कुछ हरिजन और बैकवर्ड के बारे में भी कहें।

अध्यक्ष—शान्ति। माननीय सदस्य को जो खुद बोलना है बोलें। और दूसरे की सिफारिश पर कुछ नहीं बोलें। सिफारिश या आज्ञा सदन में केवल अध्यक्ष की माननी चाहिए।

श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—अच्छी बात है हुजूर, मैं ऐसा नहीं करूंगा।

मैं यह कहने वाला था कि जो हरिजन वेलफेयर ऑफिसर हैं उन्हें जो काम करना है वह ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें हरिजन और बैकवर्ड के कामों की देख-रेख करनी चाहिए।

इसके बाद आखिरी बात जो हुजूर मुझे कहनी है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब उसे नोट करें यह वह है कि हाउस में यह बराबर कहा जाता है कि बिहार असेम्बली में इतनी बड़ी संख्या स्त्रियों की है, शायद ३५, ३६ स्त्रियां सदन में हैं तो इसके लिए श्री जवाहर लाल नेहरू से भी वाहवाही लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब इतनी स्त्रियां हमारे यहां एम० एल० ए० हैं, और उनमें से बहुत सी एम० ए० पास भी हैं, काफी सुघड़ हैं तो एक लेडी मिनिस्टर की बहाली होनी चाहिए। इससे कोई हर्ज भी नहीं होगा कि मिनिस्टर में एक लेडी मिनिस्टर का और इजाफा हो जाय क्योंकि इससे किसी मिनिस्टर का 'पे' तो घटता नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक योग्यतम लेडी एम० एल० ए० को मिनिस्टरी में लेना चाहिए। इससे सूबे बिहार के लोगों को भी संतोष होगा, और उन्हें मालूम हो जायगा कि बिहार की स्त्रियों की तरक्की आप चाहते हैं। इससे उन्हें पढ़ने-लिखने में, सोशल वर्क करने में इनकरेजमेंट मिलेगा। मेरी इतनी ही अर्ज है, इसके बाद मैं बैठ जाता हूं।

श्री दशरथ तिवारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सन् १९६०-६१ का जो

बजट पेश किया है यह मेरे ख्याल में एक रीऐक्शनरी बजट है। 'क्रियावादिता' मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी को और बढ़ाने का इसमें नक्शा दिखाई पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम होगी लेकिन देखने से मालूम होता है कि सरकार केवल मिर्गमारीच के जैसा जनता के साथ पेश आ रही है। उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे के साथ होली खेली जा रही है। मुझे दुख है कि वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है। सबसे पहले तो इस सदन के एम० एल० ए० का वेतन ही बढ़ाया गया है जो अब अढ़ाई सौ है और अपना वेतन मिनिस्टर साहबान् १,५०० रु० रखते हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या यही सोसलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी है?

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार सरकार गरीबों पर तरह-तरह का टैक्स लगा रही है और जिन पर टैक्स का बेशी भार है उनमें ९० प्रतिशत किसान और मजदूर हैं जिनकी कमर टैक्सों के भार से टूटी जा रही है। सबसे पहले जिस इलाके से मैं आया हूं उसकी ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। शाहाबाद जिले के भभुआ सबडिविजन में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका रामगढ़ और राजपुर है। वहां की जनता आज त्राहि-त्राहि कर रही है। चार वर्षों से बाढ़ और सूखार ने उनकी कमर तोड़ दी है।

१३ वर्ष स्वराज्य मिले हो गया, कहा जाता है कि बिहार राज्य में पवित्र गंगा नदी बह रही है लेकिन मेरी समझ से उस इलाके के गंगा नहीं बह रही है, उस इलाके की जनता कराह रही है। १९५६ की बाढ़ के बारे में मैंने मुख्य मंत्री से अनुनय विनय किया कि आप कृपा करके वहां चलें और देखें, इसके उन्होंने आश्वासन भी दिया इसी बिहार विधान सभा के अन्दर। एक बार बहुत सिफारिश की उनसे तो उन्होंने नोट भी कर लिया अपनी डायरी में लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

हमारे सिंचाई मंत्री, श्री दीप नारायण सिंह ने भी आश्वासन दिया। हमारे यहां कर्मनासा, दुर्गावती, कदरा तथा धर्मावती नदी की बाढ़ से लोग काफी तबाह रहते हैं। इसका जिक्र मैंने गत सत्र में असेम्बली में भी किया था, उसके लिए मैंने राजस्व मंत्री श्री विनोदानन्द झा जी से भी कहा और वे वहां गए। सिंचाई मंत्री श्री दीप नारायण सिंह भी वहां गए थे। जब मैं सदस्य नहीं था उस वक्त स्वयं मैंने बहुतों के साथ

सर पर मिट्टी ढो-ढोकर कच्चा बांध बांधा और लोगों को जगाया और हजारों एकड़ भूमि में फसल की पैदाइश उससे हुई। हमारे मंत्रियों को वहां जाने में कितना टी० ए० खर्च हुआ ? मुझे दुःख है कि किसानों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है इस बिहार विधान सभा के अन्दर। इस विधान सभा के मंत्रिगण यदि अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें तो मालूम होगा कि किस तरह वे इन पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। १९४२ में क्रांति हुई, बहुत लोग जेल गए और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप स्वराज्य मिला लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी इसमें हैं जो लोग जेल भी नहीं गए और आज ऐसे कांग्रेसी लोग मेढ़क की तरह फैले हुए हैं। आज कांग्रेस संस्था वह नहीं है जो १५ वर्ष पहले थी। आज कांग्रेसी मेढ़कों की भरमार है।

श्री नरसिंह बैठा—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ ऑर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अभी जो कांग्रेसी हैं वे बरसाती मेढ़क की तरह फैले हुए हैं और जो कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं वे बरसाती मेढ़क की तरह हैं, यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री दशरथ तिवारी—मेरा यह मतलब नहीं था लेकिन शायद यह चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात मालूम होती है।

श्री नरसिंह बैठा—मेरा फिर एक प्वाइंट आफ आर्डर है हुजूर। उन्होंने फिर अभी कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनकावाली बात मालूम होती है, यह भी अनपार्लियामेंटरी है।

अध्यक्ष—उनका प्वाइंट आफ आर्डर ठीक है इसलिए आप इन्हें वापस लें।

श्री दशरथ तिवारी—मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री नवल किशोर सिंह—उन्होंने फिर कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके संबंध में आपका फैसला पहले हो चुका है कि यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री दशरथ तिवारी—मैं तो अपने हृदय का उद्गार प्रकट कर रहा हूं और समझ रहा था कि लोग मखौल से ऐसा कह रहे हैं। जो अध्यक्ष महोदय ने वापस लेने को कहा उसे मैंने तुरत वापस ले लिया।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य का काम किसी अन्य सदस्य से बात करनी या उनसे अपने हृदय का उद्गार प्रकट करना नहीं है।

श्री दशरथ तिवारी—मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि ...

अध्यक्ष—केवल एक ही बोलनेवाले संसार में आपही हैं क्या ? आपके इतना उठने के बाद मैंने समय दिया और समय मिलने पर इतना ही बोलने में आपको दो बार अपना शब्द वापस लेना होता है चूंकि वह अनपार्लियामेंटरी है, यह तो अच्छा नहीं है ?

श्री दशरथ तिवारी—मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

अध्यक्ष—अपने क्षेत्र के बारे में जो व्यापक बात है उसी को कह सकते हैं, जो व्यापक नहीं हैं एकदम स्थानीय हैं उसको कटमोशन के लिए रखना चाहिए ।

श्री दशरथ तिवारी—मेरे क्षेत्र के लोगों को जो तकलीफ हैं उसे मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा । इसका निराकरण और क्या हो सकता है ?

हमारे इलाके, में, जहां से मैं आता हूं, सिंचाई की बिलकुल व्यवस्था नहीं है, दवा-दारू की भी व्यवस्था नहीं है और पुलिस का अत्याचार तो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है । १३ वर्ष स्वराज्य मिल ही गया, इस १३ वर्ष के अन्दर में उस इलाके से सरकार के खजाने में दुगुनी आमदनी हो गई है और उसी हिसाब से क्राइम भी चौगुनी हो गई है । यही आपके सूबे बिहार और पुलिस बिहार का विकास है, हमारे क्षेत्र में आपके पुलिस विभाग का यही नक्शा है ।

इलाज के लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं है । इसके लिए मैंने असेम्बली में सवाल भी किया था लेकिन समुचित रूप में कुछ नहीं हुआ । हमारे राजापुर थाने में ४० हजार पोपुलेशन है लेकिन वहां एक भी डिसपेंसरी नहीं है । रामगढ़ थाने में एक डिसपेंसरी है भी तो वहां एक डाक्टर हैं वे किस तरह के हैं, मैं क्या बताऊं । वहां लेडी डाक्टर है ही नहीं । प्रिगनेंसी की हालत में जो औरत होती है उसे बनारस जाना पड़ता है, नजदीक में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी हालत में मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां के लोगों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए । चूंकि इस १३ वर्ष में वहां किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ ।

बिजली के खम्भे दिखाने के लिए गाड़ दिए गए हैं लेकिन उसके आगे कोई कारंवाई नहीं हो रही है । रामगढ़ में बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ है ।

बगल में वहां एक ट्युबवेल है, उसके होने से किसानों की हालत और भी खराब हो गई है । अग्रिकलचर मिनिस्टर कह सकते हैं कि जब वहां ट्युबवेल है तो उससे फायदा होना चाहिए था लेकिन आप कह रहे हैं कि हालत खराब है, ऐसा क्यों ? वहां जो औपरेटर हैं और ड्राइवर हैं उनको घूस लेने की बीमारी है । जो आदमी पैसा देता है उसका काम कर देते हैं और जो नहीं देता है उसको कह देते हैं कि मशीन खराब है । हमारे इलाके में ग्रामीणों की हालत बहुत खराब है वहां ट्युबवेल के होने से तो और लोग कहीं के न रहे, न इधर के हुए न उधर के हुए ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैंने रामगढ़ के पास मुसलमानों की शिक्षा के लिये एक मकतब के लिये असेम्बली में प्रश्न पूछा था उसके विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है ।

बेकारी की संख्या इस राज्य में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। आज इस राज्य में पढ़े-लिखे नौजवान भी इधर-उधर अपना करम कूट रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता है।

अध्यक्ष—इसका उपाय बतावें।

श्री दशरथ तिवारी—उपाय मैं बताता हूं। इसका उपाय यही है कि आप अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज न खोलकर टेकनिकल शिक्षा का इंतजाम करें जिससे लड़के ट्रेनिंग लेकर अपनी रोजी-रोटी की समस्या हल कर सकते हैं। टेकनिकल शिक्षा प्राप्त कर वे कारखाने में जाकर काम करना शुरू कर देंगे।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ढाई सौ से कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों को जो सरकार ने १० रु० और ५ रु० मंहगी-भत्ते में बढ़ाया है उससे उन्हें कोई मदद मिलने को नहीं है। यह तो वही बात हुई कि जिस तरह से लड़के को खिलौना देकर भुला दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि उनके वेतन में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो, इसके लिये अगर मिनिस्टर, डिप्टी और एम० एल० एज० के वेतन में कमी भी हो जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि एम० एल० ए० को थर्ड क्लास में सफर करने की अनुमति हो लेकिन फ्री हो। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि कर्मचारियों का वेतन कम से कम १०० रु० और ज्यादा से ज्यादा १,००० रु० रहना चाहिये। मिनिस्टर का वेतन १,५०० से ५०० ० कर देना चाहिये।

सभा का कार्य क्रम।

BUSINESS OF THE HOUSE.

अध्यक्ष—मैं अभी दो घोषणा कर देता हूं। कल यह साधारण वाद-विवाद बजट पर समाप्त हो जायगा। २ बजे से ४ बजे तक सरकार का जवाब होगा। जैसा पूर्व सूचना है, ९ बजे सबेरे से १ बजे तक बैठना है। दूसरी घोषणा है कि शुक्रवार २६ फरवरी, १९६० को सभा की कार्रवाई नहीं होगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव :

ADJOURNMENT MOTION.

श्री शिव महादेव प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है वह बहुत जरूरी है, उसपर आपका फैसला चाहता हूं।

अध्यक्ष—बजट के जमाने में ऐसी परिपाटी है कि काम रोको प्रस्ताव नहीं लिया जाय। मैं आपको बोलने का समय देता हूं कि आप इसके बारे में कहें और आपके काम रोको प्रस्ताव को नामंजूर करता हूं।